

Allocation of time for Government Legislative Business

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform hon. Members that the Busi-

ness Advisory Committee at its meeting held today, the 10th August, 1989, allotted time for Government Legislative Business as follows:—

Business	Time allotted
1. Consideration and passing of the Constitution (Sixty-third Amendment) Bill, 1989, as passed by the Lok Sabha	2 Hours.
2. Consideration and passing of the following Bills, as passed by the Lok Sabha :—	
(a) The Constitution (Sixty-fourth Amendment) Bill, 1989	} 16 Hours. To be discussed together.
(b) The Constitution (Sixty-fifth Amendment) Bill, 1989.	

The Committee recommended that in order to complete the Government Business, the present Session of the Rajya Sabha, be extended up to the 18th August, 1989, and, accordingly, the House should sit on Monday, the 14th August, Wednesday, the 16th August, and Friday, the 18th August, 1989, and that there would be no Question Hour on these days.

I. THE BUDGET (KARNATAKA), 1989-90

II. THE KARNATAKA APPROPRIATION BILL 1989—Contd.

उपसभापति: श्री कैलाशपति मिश्र । मिश्र जी, साढ़े पांच बजे गए हैं और इस बिल के खाली दो घंटे थे, जिसमें से आपकी पार्टी के हिस्से में चार मिनट आते हैं । चार नहीं तो आप आठ मिनट में खत्म कर दोजिए ।

श्री कैलाश पति मिश्र (बिहार) : महोदया, सारा प्रतिबंध मेरे ऊपर ही लगता है क्या ? महोदया, मुझे इससे बड़ा कष्ट होता है, जब मैं खड़ा होता हूँ तो आप प्रतिबंध लगा देती हैं ।

उपसभापति: नहीं, सब के ऊपर है ।

श्री कैलाश पति मिश्र : इससे पहले तो किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा ।

उपसभापति: नहीं-नहीं, सब पर लगाऊंगी । इन लोगों को तो चार-चार मिनट दूंगी, आपको तो आठ दे रही हूँ ।

श्री कैलाश पति मिश्र : यह अच्छा नहीं है, प्रारंभ में ही आप एक वाणिज्य दे देती हैं, जिससे मूड बिगड़ जाता है ।

महोदया, मैं इस समय जरा सत्ताहीन दल के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : कर्नाटक की उस समय की जनता गवर्नमेंट की तरफ कीजिए ।

श्री कैलाश पति मिश्र : महोदया, मुझे भरोसा है कि सत्ताधारी दल के मित्र जरा शांतिपूर्वक सुनेंगे । राज्य सरकार का बजट संसद के अंदर पारित हो रहा है और राज्य का बजट संसद में पारित करने में सत्ताधारी दल के पक्ष में काफी उत्साह और उत्साह दिखाई दे रहा है, शायद यह उनके लिए गौरव का दिन है । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य सरकार का बजट केन्द्र में पारित होने के लिए आता है तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य का दिन नहीं होता ।

महोदया, राज्यपाल शासन बना हुआ है कर्नाटक में। बैठे हुए राज्यपाल महोदय, मैं तम नहीं लेना चाहता, होम स्टेट मिनिस्टर के नाते से यहां देखा है, मैं बिहार से आता हूं, बिहार में राज्यपाल के नाते से उन्हें देखा है, मेरी समझ में नहीं आया कि अचानक बिहार से उठाकर के कर्नाटक उस समय क्यों उन्हें भेजने की आवश्यकता पड़ी? लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे कामों के लिए कोई समय व्यक्ति ही चाहिए। राज्यपाल महोदय कर्नाटक पहुंच गए। राज्यपालों की व्यवस्था आजकल जिस प्रकार से चल रही है वह देखकर के एक आश्चर्य लग रहा है। देश के अंदर की ऐसी संस्थाएं, जिनकी कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को समाप्त करना, मानों इसके लिए सत्ताधारी दल ने कमर कस ली है। राज्यपाल आज कैसे भेजे जा रहे हैं कि जहां कोई डिप्टी मिनिस्टर है उसको उठाकर भेज दिया केरल, कोई स्टेट मिनिस्टर है उसको उठाकर भेज दिया दूसरे प्रांत में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को उठाकर भेज दिया किसी तीसरे प्रांत में। जिस समय यह होम मिनिस्टर थे, समझने की आवश्यकता नहीं है कि वह किस दल के थे शायद और नीचे जाएंगे तो दल के पदाधिकारी के नाते भी उन्होंने किसी न किसी राज्य में काम किया होगा। राज्यपालों की मर्यादा इस परिपाटी के अनुसार किस तरह समाप्त की जा रही है कि देश के लोकतंत्र के ऊपर ही खतरा दिखाई दे रहा है।

महोदय, मुझे कभी-कभी लगता है, मैं बिहार से आता हूं, पटना हाईकोर्ट में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 68,000 केसेज पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं, टोटल स्ट्रेंथ हाईकोर्ट में 39 हैं और 16 जजों की रिक्तियां वैसे की वैसे वर्षों से पड़ी हुई हैं। आप कल्पना कीजिए टोटल स्ट्रेंथ 39 और उसमें 16 स्थान खाली, 68,000 केसेज पेंडिंग... (व्यवधान)...

उपसभापति: कहां कर्नाटक में?

ठाकुर जगतपाल सिंह: पटना कोई कर्नाटक में है क्या?... (व्यवधान)...

श्री कैलाश पति मिश्र: मैं उसी तारतम्य में बता रहा हूं। अच्छा छोड़ दोजिए आप बिहार को, दिल्ली में ही सुप्रीम-कोर्ट के अंदर 1,30,000 केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की जगह खाली है, हाईकोर्ट के जजों की जगह खाली है। मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल को कठिनाई हो रही है कि किसी डिप्टी मिनिस्टर को या स्टेट मिनिस्टर को उठाकर गवर्नर तो बना देते हैं, लेकिन पार्टी में कोई सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी नहीं मिलता है, जिसको हाईकोर्ट का जज लेकर बना दें और तभी चलकर के स्थानों की भरती हो जाएगी।

महोदया, ऐसे गलत तरीकों के कारण देश के लोकतंत्र के स्तंभ एक-एक करके टूटते चले जा रहे हैं। आप वहां गए, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है कि चुनी हुई सरकार को जब समाप्त करना चाहिए तो फ्लोर पर ड्राइल लेकर समाप्त करना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कर्नाटक में विधानसभा के फ्लोर के ऊपर सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है, किस तारीख को, किस सप्ताह में, किस महीने में ड्राइल करके उस सरकार को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? इसकी अगर जानकारी दें तो बहुत अच्छी बात होगी।

महोदया, मैं काफी देर से यहां भाषण सुन रहा हूं और ऐसा लगता है कि कर्नाटक के अंदर केवल खाई और गड्ढे थे और जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, कर्नाटक उठते-उठते आकाश में चला गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हम यहां संसद में बैठकर चाहे जो बहस करें, कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के नर-नारी नाटक के सारे पहलुओं को देख रहे हैं और उनके मन में जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वह हो रही है। महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने राष्ट्रपति शासन में कर्नाटक को पाताल से लेकर ऊपर आकाश तक उठा दिया है, तो फिर चुनाव कराने में क्यों हिचक रहे हैं? कितने दिन चुनाव नहीं कराएंगे? राष्ट्रपति शासन के 4 महीने निकल गए हैं। राष्ट्रपति शासन होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार 6 महीने के

[श्री कैलाश पति मिश्र]

अंदर वहाँ चुनी हुई सरकार चाहिए। क्या आप हिम्मत के साथ कहने के लिए तैयार हैं कि 6 महीने के अंदर कर्नाटक के अंदर चुनाव होंगे? आपने कर्नाटक की स्वर्ण बना दिया है। कर्नाटक का एक-एक नागरिक आपसे इतना प्रसन्न हो गया है कि आप-ही-आप उसकी आँखों में, उसके हृदय में दिखायी देते हैं। इससे अच्छा अबसर आपको क्या मिलेगा। जब आप अपने पक्ष में इतने तर्क दे रहे हैं तो वहाँ 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए और विजयी होकर आइए अपने आप सबवाई प्रमाणित हो जाएगी। आप में चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ; राष्ट्रपति महोदय से मेरा परिचय है, वे सलाह करने के लिए दिल्ली आए थे कि चुनाव कराए जाएँ या नहीं? वे केन्द्र सरकार को निराश कर गए हैं कि अभी चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो पहले जितनी पराजय हुई थी उससे अधिक पराजय हो जाएगी। महोदय, मैं अप्रह्व कर रहा हूँ, कि सरकार घोषणा करे। आप आज इतनी ही घोषणा कर दीजिए कि 6 महीने के अंदर कर्नाटक में निर्वाचित सरकार खड़ी हो जाएगी।

महोदय, आप यह बता रहे थे कि कर्नाटक के अंदर आर्थिक दिवाला निकल गया है। मुझे हंसी आ रही थी यह सुनकर। आज सत्ताधारी दल को केवल विरोधी दल की जहाँ सरकार बनो हुई है, वहीं यह दिखायी दे रहा है। कांग्रेस शासित एक भी प्रदेश सत्ताधारी दल को दिखायी नहीं दे रहा है। आपने जितनी खामियाँ और जितनी फिजूल-खर्ची के उदाहरण बताए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि सारे देश की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ आप वहाँ चलकर देखिए। आपने जितना कर्नाटक के बारे में कहा उससे अगर सौ गुनी आर्थिक दुर्व्यवस्था बिहार में नहीं हुई होगी, जहाँ आपको सरकार है, आपका मंत्रिमंडल और मुख्य मंत्री है तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूँगा। यह घोषणा करने के लिए मैं तैयार हूँ। केवल गैर कांग्रेसी सरकार आपको दिखायी दे रही है। आप खोज-खोजकर ऐसे उदाहरण निकालते हैं जिनकी कि तुक नहीं है।

आप सरकारी कमीशन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। केन्द्र के साथ में अधिक पूँजी कितनी रहे और राज्य में किस सीमा या अनुपात में उसका वितरण हो, इस पर आप बहुत के लिए तैयार नहीं हैं। केन्द्र के हाथ में कितनी सत्ता रहे और राज्य सरकार के हाथ में कितनी सत्ता दीजिएगा इस बात को सानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बिसे-पिट नियम चला रहे हैं।

महोदय, मैं लंबी कहानी कहने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यदि रखिए किसी एक राज्य के ऊपर आर्थिक दुर्व्यवस्था का आरोप लगाएँ उसके तीन-चार-छ साल राज करने के कारण, लेकिन झूलिए मत कि आप सन् 1947 के बाद से गद्दी पर बैठे हैं। आपने एक-एक कर आर्थिक कवम उठाए हैं, उसका दुष्परिणाम पूरे देश के ऊपर होता हुआ दिखायी देता है। आपने कमीशन बिठाया है। मेरे मित्र बैठे हुए हैं। मैंने टर्म्स आफ रिफरेंस अभी पढ़े और देखे हैं। मुझे हंसी आ रही थी कि देश में क्या हो रहा है।

भ्रष्टाचार अगर प्रशासन में नहीं तो उठकर के उसकी जांच होनी चाहिए भ्रष्टाचारी को बाहर लाना चाहिए और जो उचित पनिशमेंट हो वह देनी चाहिए अगर, आपने जो कमीशन बैठाए हैं, इसमें से आप कुछ निकालने वाले नहीं हैं। अंत में कह दूँगे कि कमीशन को तो अनुशंका होती है, मेंडेरी नहीं है रिक्मेंडेरी है। केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए यह कदम आप उठा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के अंदर कुछ नैतिकता रहने दीजिए... (घंटी)... कमीशन का राजनीतिकरण मत बनाइए। आप केवल राजनीतिकरण के चक्कर में रहे हैं, देश के संचालन के लिए आप अपना दिमाग नहीं दीड़ा रहे हैं।

इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपने राष्ट्रपति शासन लगाकर जो पाप किया है, संसद में आप सत्य के पक्ष में चल रहे हैं तो आप आज यह

बोवणा करिए कि 6 महीने के अंदर वहाँ पर लोकप्रिय सरकार बनेगी, निर्वाचन से सरकार बनेगी। आप उसमें जीत जाइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri V. Narayanasamy. Needless to say, please be rather brief because it is already quarter to six. Be to the point.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam Deputy Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak on the Karnataka budget.

The Karnataka State, as far as financial position is concerned, is in a bad shape. The reasons have been explained by the previous speakers from my side. I would like to say that in no State was a budget passed for six months but in Karnataka, after the Janata Government came to power there, in March 1989 the vote on account was passed only for six months. They have actually made history in this regard.

As far as revenue in Karnataka is concerned, in 1983-84 it was Rs. 1,484 crores. In 1988-89 it was Rs. 2,200 crores. Now, in 1989-90, it is expected to be Rs. 2,600 crores. From sales tax alone they have been collecting Rs. 1,000 crores. And with all this money the State Government was not in a position to manage the situation.

I would like to say that the Central Government had given them an allocation for the purpose of drought relief. The honourable Member, Hanumanthappa, also has said that the Chief Minister was not visiting the drought-affected areas. Only after the Prime Minister's visit to those areas was he compelled to go to the various areas which were affected by drought. I am pained to say that even the amount that has been sanctioned by the Centre was not fully utilized. Out of Rs. 37.34 crores sanctioned by the Central Government, the State Gov-

ernment had spent only Rs. 19.70 crores. Just see the utter carelessness of their not taking into consideration the situation in Karnataka, especially in the drought-affected areas. That is how the State Government was functioning.

Apart from what I have already said, the scandals in Karnataka can be divided into four categories. One is with regard to telephone tapping. Not even the Ministers of Mr. Hegde's Cabinet were spared. The honourable leader in the opposition, Mr. Gurupadaswamy is not sitting here at the moment; he was there sometime back. Even the telephone of the present Janata leader, Mr. Deve Gowda and the telephones of so many other people were tapped. Even the telephone of Mr. Chandra Shekhar, a senior leader, was tapped. The telephone of Mr. Ajit Singh was tapped. The telephones of all these leaders were tapped by Mr. Ramakrishna Hegde for his own political ends.

If you go through the strategy adopted by them in the land scandal, you will find that the Urban Land Ceiling Act is enforced in Karnataka, especially in Bangalore, but the strategy was that no one should sell the land which is within the city limits because it is covered by the Urban Land Ceiling Act or is under the green belt area. The Government used to send notices to the parties that they are going to acquire land. Immediately instructions will be issued that this land will be given to societies, all fictitious societies. Those societies have taken the land, and with that they have been thriving. It is an indirect way of circumventing the land regulation. Twenty-two thousand hectares of land has been given to societies. Madam, those societies also engaged middlemen, and through the middlemen the Chief Minister and his Cabinet colleagues were acting. By this, crores of rupees have gone into the coffers of the Chief Minister, Mr. Ramakrishna Hegde, and his Cabinet colleagues during the Janata rule.

[Shri V. Narayanasamy]

Apart from that, as far the enquiry is concerned, a committee was appointed. The G. K. Rao Committee was appointed. The Committee was going into the allegations. While the enquiry was going on, the Chief Minister's office sent a letter. In that letter, it has been mentioned that the State Government need not unnecessarily enter into the controversy. This order is relating to the co-operative societies. Therefore, the Secretary wrote the letter. But, Madam, Mr. Ekanthaiah, who was the Minister for Co-operation—Mr. Hanumanthappa says that he is from Chitradurga District from where he is also coming—saw to it that the enquiry was proceeding. Madam, even at the time when the G. K. Rao Committee was to submit its report, what happened was that all attempts were made, even by the Bommai Government, to stop the report. But, fortunately, for the Chief Minister the report came. Madam, in that report it was very clear that the relatives and friends and known persons of Mr. Ramakrishna Hegde have been favoured. Madam, Mr. Ekanthaiah, the Minister at that time was punished, and he was not taken at the time of the expansion of the Ministry the next time. Madam, this is the hard fact which nobody can deny.

Madam, apart from that, I take the liquor deal. I will give the details of how you have swindled money in Karnataka. As far as liquor is concerned, they have got the term "seconds." Only the production of the first bottle is taxed. Other items they have been manufacturing in 1:15 ratio. Madam, it has been proved that the Chief Minister is a darling of the liquor barons of Karnataka. What happened, is, the tax evasion was 100 per cent. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I checked up. "Darling" is parliamentary.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, the evasion was 100 per cent,

in which 99 per cent was going to the coffers of the persons who have been involved in the deal, and only 1 per cent was going to the Chief Minister.

Madam, I will give the figures which will be startling. As far as arrack is concerned, the State was getting a revenue in 1987-88—I will take the figures of 1987-88—of Rs. 135.45 crores; in 1988-89, Rs. 137.75 crores. As far as other items, as far as the IMFL, are concerned, the State exchequer was getting Rs. 41.43 crores in 1987-88 and in 1988-89 Rs. 47.92 crores. As far as the duty on liquor essentially the IMFL is concerned, it will always be more. The income derived by the State Government from the IMFL liquor will be more compared to that of arrack. By allowing "seconds" to be manufactured and sold in the market, evading the duty, the Janata Government, and when Mr. Bommai came it was the Janata Dal Government, and I could not distinguish between the Janata and the Janata Dal, both the Governments were patronising this business and earning crores of rupees. After the issue was raised in the House, I would like to quote only two lines about the reaction of the former Chief Minister, Shri Ramakrishna Hegde. What was the reaction? He simply said:

"Today it was his Government that took maximum number of effective steps to stop sale of seconds in liquor."

It is a blatant lie. It was only during the period of Shri Ramakrishna Hegde that the seconds were sold very freely in the market without paying any taxes and Ramakrishna Hegde had patronised it and today he has become a person of Rs. 200 crores. That money is not only in India, but is also in foreign countries. Therefore, in all the fields, whether it is in liquor or cooperative societies or even in sanctioning of the colleges, on all they have been getting money.

If you see the paper and if you hear his speech on a platform you will see that he speaks of value-based politics. He says there should be clean image in political life. This is what the clean image and value-based politics is which Janata Party and Janta Dal are preaching to the nation and also to the people of the country. They should be ashamed of it. A person in public life getting money out of each and every deal should quit politics and go away to save the public from all these things. But unfortunately, such kind of people are preaching politics to others. Therefore, I request the Central Government since the President's rule in there now, all the cases of irregularities, corruption, malpractice and cheating the public and filling their coffers should be brought out. The Government should take stern action against the guilty.

An hon. Member who spoke from our side stated that the State coffers have become empty. I would like to say only one word about the Government servants. The State Government servants were not paid the increased DA by the State Government for more than four years. They had been given National Savings Certificates instead. What will a Class IV Government servant do with the National Savings Certificates? Is it going to feed him? Moreover no bonus was paid to them. In all the Congress-ruled States, the State Government employees are getting 26 days' bonus, but the State Government of Karnataka had not paid bonus to its employees in spite of their demand for it. They agitated in favour of their demand. Moreover, they went on strike for more than one month to press their demand, but the State Government was simply keeping quiet. When the Governor's rule was introduced, he immediately announced that cash will be given to them in lieu of the amount accumulated by way of National Savings Certificates.

The State Exchequer was completely emptied by them. Apart from getting

money from outside, they have also taken money out of the coffers of the Karnataka exchequer. Therefore, the duty is cast upon the Finance Minister and also on the Governor of Karnataka to see that the State administration is made sound financially and they have to ensure the State's industrial growth. I hope the Central Government will give all the assistance to the Government of Karnataka for bringing this derailed State back on its rails.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: This is for the second time that we are discussing a State Budget in the House. It is very unfortunate that we are discussing the Appropriation Bill of a State which has been put under President's rule in a very undemocratic way. In the most unethical and undemocratic way the Karnataka Government was toppled and President's rule was imposed.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): This House is discussing Karnataka budget because the Janata Party failed in that State. They were devided. Finally, it came under President's rule.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I am coming to the point. My time is very short but even then I will tell you about the point. My question is: Can any Member of the Treasury Benches say that the States ruled by the Congress-(1) are giving real happiness, real El Dorado to those people or are they ruling without corruption? We can give a big list of corruption charges of those States. I know many of the States, even my State, how the affairs of those States are running. I do not want to go into the details because of constraint of time. Madam, you have indicated the time allotted to my party and that is why I will not go into the

[Shrimati Bijoya Chakravarty]

details. I know that in 1970-71 the Governors' Conference recommended that majority of the ruling party should be tested only on the floor of the Assembly but this is not being done in the case of non-Congress (I) States and they are being toppled. Besides this, even after the recommendations of the Sarkaria Commission, we have seen how the Governors are appointed, how the Governors are acting in the non-Congress (I) States. They are acting just like agents of the Centre and as Congress (I) people. Madam, I want to mention only one example, not of the present Government at the Centre but after 1971 elections to Assembly in Bengal. Instead of inviting the largest single party enjoying majority, Mr. Jyoti Basu who was the leader of the Left Front party, Mr. Ajoy Mukherjee was invited to form the Government. So, Madam, this is only one example I put forward to prove my point. I do not want to speak about corruption, giving suggestions and counter-suggestions because much water has flowed into Ganga and Cauvery. But I want to say, Madam, living in a glass-house one should not throw stones at others. To justify the President's rule in Karnataka, the Members sitting on the left side to me levelled charges which are not proved ones. But what about the CAG report? It has clearly pointed out the corruption of the ruling party at the Centre. The CAG report pointed out directly to the person sitting in the highest office of the country. In spite of the Opposition parties demanding resignation of Mr. Rajiv Gandhi, why he has not resigned?

THAKUR JAGATPAL SINGH: Madam, it is not a fact.

PROF. SURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): He is not resigning. That is a fact. Has he resigned? Is it not a fact that he has not resigned?

ठाकुर जगतपाल सिंह : आपको यह मोका नहीं मिलगा ... (व्यवधान)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: The Centre can topple a non-Congress (I) Government because of unfounded charges whereas corruption which is a Constitutional body against the ruling party at the Centre and yet the Government has not yet resigned. That is my point.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: He has made an exposure. That is why he has to resign.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: (Time bell rings) I will take only half-a-minute. Madam, we have seen the performance of the Janata Government that had come to power in 1983. The performance was better than the Congress-I Government that ruled the State until 1983. We have seen that 25 per cent of the seats are reserved for women in the local bodies and moreover those people who are constituting less than 1 per cent are given a chance and nominated to the local bodies. Madam, this provision of passing the budget of a State here should be stopped and the elections should be held as early as possible in Karnataka. Thank you.

SHRI SUKOMAL SEN: Madam, how many speakers are there?

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will pass this Bill because it is a money Bill. We can remove the names.

6.00 P.M.

SHRI SUKOMAL SEN: Enough harm has been done to Karnataka. What more do you want? They have said so many things. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: The names can be removed by me. If you want the Bill to be passed ... (Interruptions) ... I can ask the Minister to reply ... (Interruptions) ...

SHRI M. M. JACOB: No, no. Mr. K. G. Maheswarappa, will not agree. I want to listen to him.

1989-90 and

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, he has no time. (Interruptions)...

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: At least, let us do justice to Karnataka Budget. No Karnataka man has spoken... (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Tomorrow, we have very little time. It is Private Members' Day and we have to finish it today. (Interruption)...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Therefore, it has to be passed today. That is the only justice to the Bill.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: No, no. The Treasury Benches people took forty-five minutes to one hour, (Interruptions)... Tomorrow, we will continue... (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let Shrimati Syeda Anwara Taimur make her maiden speech at the fag end of the day.

SHRIMATI SYEDA ANWARA TAIMUR (Nominated): Madam, this is not my maiden speech. In purport of Karnataka Budget I want to speak a few words. I shall be very brief, Madam, because already our party people have elaborately spoken about corruption and other things. My colleague, Shrimati Bijoya Chakravarty has said that the State Government of Karnataka was ousted undemocratically and the President's rule was promulgated. I would like to say that it was because of the Janata Party misrule that the economic conditions deteriorated and rampant corruption, mismanagement affected the progress of the State and when the progress of the State was hampered and stagnated, unemployment problem increased, people became insecure and restless and even the party legislators revolted. As a result of all this, the Janata Government fell and President's rule was imposed. It is not because the Central Government wanted to have Presidential rule there that the State

Government of Karnataka was ousted. Our hon. colleague, Mr. H. Hanumanthappa has stated it elaborately with documents about the performance of the Janata Government in Karnataka. Almost all the welfare schemes were stagnant. The widows' pensions were stopped, the old age pensions were not paid. Almost all the developmental programmes were stagnant and now, I would like to say that by imposing the Presidential rule, this State has been saved. Hon. Shrimati Margaret Alva also stated with documents and facts and figures about the condition of the officials, the low-paid officials, like the police, the security personnel. Their TA and DA were stopped. The primary school teachers were also not paid. How these low-paid employees can run their lives if the condition of the Government was like this? The treasury was empty and due to revolt made by the party legislators, this Government fell. Now, I do not want to repeat the corruption charges against the State Government which have so vividly and elaborately been discussed by my colleagues. Now, I want to say that sufficient funds which have been allotted for the State of Karnataka and the Jawahar Rozgar Yojana will particularly give benefit to the backward-classes, women and other weaker sections of the society. This scheme will give employment at least to one person in a family. It will go a long way to eradicate poverty. In this scheme, 80 per cent funds will be provided by the Union Government and 20 per cent by the State Government. I hope, the allocation made for the development of women and child welfare would be implemented properly. As democracy is our tradition, I think elections should be held in Karnataka as early as possible so that the people may participate in the nation-building task. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Prof. Sourendra Bhattacharjee. Kindly confine yourself to three minutes.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Perhaps one minute also might do to oppose, Madam. But, anyway, let me hope that you will not watch out with stop-watch.

As I was hearing some of the speeches from the treasury benches, their display of self-righteousness, I was reminded of a Bengali saying meaning the mother of a thief shouts much: My colleague here is giving the Bengali for it. 'chorer mayer bara gala'. But after that, there is another thing which I do not want to bring in. That will be instead of eating the banana doing something else. The question is the initiator of the entire process of destabilisation which has been haunting our Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. The process of destabilisation in Karnataka was initiated by a person. Mr. Venkatasubbiah, who hails from a neighbouring State, but who went as the Governor of Bihar. (Interruptions)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, I am sorry... (Interruption)

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: There can be no point of order.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am not on a point of order. I am on a matter of correction. Their own party people have said the reasons for the failure of the Government. Nowhere, nobody, so far referred to Mr. Venkatasubbiah as... (Interruption)

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: I was telling of the unenviable record of the present Governor of Karnataka when he was in Bihar.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I must remind the hon. Member that he should not bring the name of the Governor. You can talk about Karnataka, but not the Governor. We are not discussing the conduct of the Governor.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: This time, I have not added the name. I have said, when he was the Governor of Bihar, he had an unenviable record of dismissing seven vice-chancellors. (Interruptions)

SHRI SUKOMAL SEN: So many times names have been taken. (Interruption)... everything has been taken in the House. Why not Venkatasubbiah?

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: No. No question of name. (Interruption).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a second, please. I want to remind the hon. Member. You are speaking on the Karnataka Bill. We should confine ourselves to Karnataka. What anybody did anywhere else is not to be discussed over here at this point of time. Please confine yourself to what has been happening in Karnataka.

SHRI MOTURU HANUMANTHARAO: We are discussing in Delhi, in Parliament. The Budget is proposed by the Central Government. So we must speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That we are discussing within the rules. We are not doing anything beyond the rules (Interruptions).

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: When the seasoned... it was within the rules.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. It will not go on record.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: *

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. No. It will not go on record. Bihar is not in Karnataka.

*Not recorded.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: I concede that it was under the rules. But,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please talk relevance. Do not talk irrelevance. What happened to Vice-Chancellors in Bihar is not our concern just now.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: It is not a question of Bihar. It is a question of supersession, dismissal. Here was a dismissal there was a dismissal. Now the question is we discussed at length the inequity of the step which was taken in Karnataka at that time. But then we were given to understand that elections in Karnataka would be held at a very early date. My previous speaker, the honourable Shrimati Anwara Taimur, who herself had been a Chief Minister, expressed the hope that elections would be held as early as possible. Now, the term 'as early as possible' is a term which can be stretched anyway one likes. As things stand, when Karnataka is under the Centre, the ruling party at the Centre or its State branch do not talk of elections there. So hoping for elections there and a return of the popular rule in Karnataka may be a far cry. I would, therefore, urge upon the Minister who is here to expound the policy of his Government of destabilisation or stabilisation, to assure us on this point that elections would be held in Karnataka within six months and the spell of President's rule won't be extended in Karnataka after October. Thank you.

उपसभापति: डा० रत्नाकर पाण्डेय आप भी कृपया समय का ध्यान रखियेगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): आपके आदेश का पालन करूंगा... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): ...सहोदरों... (व्यवधान)

उपसभापति: आप अनफावनेटली कांग्रेस पार्टी के मੈम्बर नहीं हैं। उनको पार्टी का टाइटम मिलता है। आपकी पार्टी के आप अकेले हैं तो आपके हिससे का टाइटम आपको मिलेगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय उपसभापति जी, कर्नाटक सरकार के वर्ष 1989-90 के अनुमानित बजट में चालू वर्ष के लिए 3429.24 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है। राजस्व लेख में 3551.40 करोड़ का व्यय होने का अनुमान है और इसके फलस्वरूप 122.16 करोड़ का राजस्व घाटा रहेगा 1580.27 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां होने का अनुमान है और पूंजीगत व्यय 1034.41 करोड़ होने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष के लिए राजस्व और पूंजी संबंधी कुल लेन देनों में 170.30 करोड़ के घाटे होने का अनुमान है।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 21 अप्रैल, 1989, को जारी की गयी उद्घोषणा के परिणाम स्वरूप कर्नाटक राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद अथवा संसद के प्राधिकार द्वारा हो रहा है। इसलिए इस बजट पर चर्चा करने का जो आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। माननीय उपसभापति जी, मैं बड़े ध्यान अपने समस्त पूर्व वक्ताओं के भाषण और जो कुछ कर्नाटक सरकार के संबंध में कहा गया उसको सुन रहा था। वहां के जन प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गयी सरकार आपस में लड़ती थी। वहां जूते में दाल बांटी जा रही थी। जनता पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ इतनी रस्साकसी थी कि वे अपनी को गिराने में लगे हुए थे... (व्यवधान) भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो मैं आऊंगा... (व्यवधान) जूते में दाल बांटना, यह मुद्दा है... (व्यवधान)

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Madam, can the word "jhoota" be used?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is only an idiom.

SOME HON. MEMBERS: It is an idiom... (Interruptions)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय: आपन डिबेट शुरू की है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो असंसदीय हो, गौड़ा जी। मैंने बता दिया है। मैडम भी आपको बता देंगी।

मैं आपको कह रहा था कि कर्नाटक सरकार का बजट जो प्रस्तुत हुआ है, वह वही बजट है जो जनता दल की सरकार ने खुद बनाया था और कर्नाटक विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री, माननीय बमई जी की सरकार गिर जाने से बजट पास न हो सका और संविधान की धारा 356 के अंतर्गत इसे संसद में पेश करना पड़ा है।

वित्त राज्य मंत्री जी ने लोक सभा में इसे प्रस्तुत किया था और फाइनेंशल मिसमेनेजमेंट शब्द मैं वित्त मंत्री का कोट कर रहा हूँ—फाइनेंशल मिसमेनेजमेंट—का नाम दिया था कि इसके कारण वहां की सरकार भंग हुई और वहां की सरकार को कर चोरी न रोकने के लिए भी दोषी ठहराया गया था।

माननीय महोदया, मैं उस अंश को उद्धृत करना चाहूंगा जिसके कारण सरकार ने यह अंकुश लगाया है। साफ कहा गया है आयोजन परिव्यय के सातवें प्वाइंट में कि—

“जनता सरकार अपने पीछे भारी बजटीय घाटा और अपूर्व दायित्वों की वसीयत छोड़ गई है। राजकोषीय अव्यवस्था और अनुशासनहीनता के अलावा, इस बात पर विश्वास करने के सबूत मौजूद हैं कि जनता सरकार करों की चोरी रोकने के बारे में सतर्क नहीं थी और स्पष्ट है कि शराब के संबंध में बड़े पैमाने पर राज उत्पाद शुल्क की चोरी की गई है।

इस प्रकार शराब विनिर्माताओं को बेहिसाब भारी आय हुई है। इससे जनता सरकार के अधीन कर्नाटक में किसी अच्छी राजकोषीय प्रणाली का पता नहीं चलता है।

राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उसके पश्चात् स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य प्रशासन भरसक प्रयत्न कर रहा है। राजस्व में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। कर संग्रहण करने वाले अधिकरणों के लिए उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कर निधियों और कार्य विधियों में कमियों को दूर करने और करों में चोरी को कम करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।”

इसके फलस्वरूप वह राशि प्राप्त होगी जिसका उपयोग कर्नाटक के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाएगा।

माननीय उपसभापति जी, जो कर चोरी करने वाली सरकार थी, इसी सदन में हमने जीरो आवर में उठाया था कि पंद्रह लाख रुपए रोज शराब के एक्साइज से होता कर्नाटक में लेकर, शराब से, उस एक्साइज को तीन वर्षों तक छोड़ा गया है। तीन सौ करोड़ रुपए के कर की चोरी की गई और प्रति वर्ष यह हुआ है।

श्री राम अवधेश सिंह: कितने का?

डा० रत्नाकर पाण्डेय: लिख लो, तीन सौ करोड़ रुपए। पंद्रह लाख रुपए रोज की चोरी हुई है और इसलिए यह कर चोरी की गई है।

अभी हमारे माननीय सदस्य जमीन के घोटेले की बात कर रहे थे और कर्नाटक सरकार करोड़ों रुपए के बिल का भुगतान नहीं कर पाई। साठ-साठ, दो-दो सौ रुपए के चैक जिस सरकार के वापिस हो जायें, उसकी क्रेडिटवॉर्निंस समाप्त हो गई थी। ऐसी दीवालिया, बैक्रेफ्ट और एक तरह से समाज में मुंह नहीं दिखाने

लायक सरकार इस देश में हो, यह चिंता की बात थी केन्द्रीय सरकार के लिए ।

जिस सरकार के कर्मचारियों का बोनस न हो, जिस सरकार के बारे में बड़े विस्तार से हनुमन्तप्पा जी ने सिद्ध किया है--मैंडम एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

हमारे हेगड़े जी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के छात्र हैं ; उन्हें उस संस्था में पढ़ने का मौका मिला है जहाँ नरेन्द्र देव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सम्पूर्णानन्द जी, डा० केसकर जैसे लोग वहाँ थे, हिन्दी के प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद जी भी वहाँ थे और वहाँ का छात्र जो सामाजिक उत्थान के लिए स्वतंत्रता की बलिदेवी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कामना से काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, वहाँ का छात्र एक हजार हिंदी के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार ने सौ प्रतिशत राशि देने की स्वीकृति दी, लेकिन माननीय उपसभापति जी, अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई ।

उपसभापति : कहां ?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : कर्नाटक में केन्द्र सरकार ने राजभाषा हिंदी और सम्पर्क भाषा हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए एक हजार टीचर्स रखने के लिए सेक्शन किए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I want make sure that it is about Karnataka. Whether it is Karnataka or some other place, I want to be sure about.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैंडम मैं कर्नाटक की बात करूंगा, दूसरी बात नहीं करूंगा । तो उनकी नियुक्ति नहीं हुई । कर्नाटक में पुरन्दर दास की धरती है, कर्नाटक अपने चंदन के लिए अपने सिल्क के लिए, टीपू सुल्तान के लिए चामुंडा जी के लिए प्रसिद्ध है । वहाँ पर हुन्दी के अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई और प्रतिवर्ष इस राजस्व का सदुपयोग हीं किया गया जो केन्द्र सरकार ने दिया । इस प्रकार राजभाषा के साथ भी तुत बड़ा अन्याय और घोटाला किया या । मैं नहीं समझता हूँ कि इस सदन के लिए एक माननीय सदस्य जो अभी

अमरीका में जा कर के घोषणा किए थे, कर्नाटक से वे आते हैं मैंडम और उस सत्य को रिकार्ड कराने की अनुमति मैं आपसे चाहता हूँ । न कर्नाटक के वह रहने वाले हैं न राम कृष्ण हेगड़े के दल में उनका विश्वास न राम कृष्ण हेगड़े की जाति-धिरादरी के हैं ... (व्यवधान) न राम कृष्ण हेगड़े की भाषा बोलना जानती हैं न जाने कौन सी रिश्तेदारी राम कृष्ण हेगड़े से उस व्यक्ति की है कि उसे इस सदन में लाया गया । इस सदन के हमारे माननीय सदस्य ओपोजिशन के लीडर श्री गुरुपदस्वामी जी की चिंता में देख रहा था, आप माननीया उपसभापति जी चेंबर पर नहीं थीं, तो वे साथे पर हाथ रख कर बैठे हुए थे कि क्या हो गया । जो व्यक्ति राज्य सभा के अपने नेता का भी फोन टेप कराता हो वैसे व्यक्ति को जनतंत्र में कितना विश्वास है यह किसी से छिपा नहीं है । जान-बूझ करके जो सरकारी बिल थे उनको रोक दिया गया और उनमें घाटा दिखाया गया । तीन सौ करोड़ रुपये की शराब की कर चोरी की गई और जनता की जूबां पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री हेगड़े जी के काले-कारनामे आज हैं । इस शराब की चोरी में जनता सरकार के तब के मुख्य मंत्री हेगड़े जी ने शराब बनाने वालों से करोड़ रुपये वसू किए हैं । इतना ही नहीं बैंगलूर विकास प्राधिकरण का दुरुपयोग करके हजारों एकड़ जमीन उन्होंने रुपये ले करके दिलवाई और उसका हिसाब-किताब क्या है आज तक किसी को उन्होंने नहीं बताया । प्रेस के नाम अपना बयान जारी करते हुए अभी जीरो आवर में हम लोगों ने उठाया था उसकी फटिंग है मैंडम आप समय नहीं दे रही हैं नहीं तो मैं उसमें से उद्धृत करता । "डैक्कन हैरल्ड" में बड़े विस्तार से माननीय हेगड़े जी का दिया है और उनसे के हर बर्ड को हर सेंटेस को इस सदन के इश्य से हथ वेलेंज करना चाहते हैं देश के किसी भी फोरम पर वह हम से तर्क कर सकते हैं और उनके सारे झूठ धनाने के कासे कारनामों की धड़की उड़ाकर हम रख देंगे । माननीया महोदया श्री हेगड़े के मुख्य मंत्री बनने के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और आर्थिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उनके परिणाम देर से हासिल

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

हुए। सोभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उसका जो कुछ फायदा हमने जनता को देना था वह हेगड़े जी ने स्वयं उन योजनाओं का फायदा अपने लिए उठाया और अपने और अपने परिवार वालों के पोषण के लिए दूसरे लोगों को दूसरे शब्दों में रिश्वत लेने और देने में वह माहिर है। इसीलिए इस संसद में और इस सभा में एक माननीय सदस्य ने उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा प्रदेश कर्नाटक छोड़ कर बम्बई की अदालत में दायर किया और दो करोड़ का मानहानि का दावा दायर किया है। सहोदया बिजली की योजनाओं के लिए जो टेंडर काल किए राम कृष्ण हेगड़े ने वह सब बिना स्वीकृति के मतमानी से दिया और करोड़ों रुपया उसमें उन्होंने कराया। ग्राह्य अपनी और अपने परिवार वालों की कार-गुजारियों पर पर्दा डालने के लिए रिश्वत के तौर पर एक फौजदारी वकील को अपने मुख्य मंत्री काल में कर्नाटक से उन्होंने राज्य सभा का टिकट दिलवाया। वह व्यक्ति आज विदेश में अमरीका में जा करके कहता है कि बी० पी० सिंह भारत के प्रधान मंत्री होंगे। मैंडम क्या अमरीका किसी को भारत का प्रधान मंत्री बनाएगा या भारत की जनता बनाएगी? राम कृष्ण हेगड़े जो रिश्तेदार से भी अधिक निकट हैं उस संसद के उसको कहते हैं कि वह इस देश का दूसरा नेता होगा। जाकर विदेशों में बहुत बड़ी गलती की है। जनतंत्र के नाम पर इतना बड़ा तमाचा खींचकर राम कृष्ण हेगड़े ने मारा है जो इंदिरा गांधी के हत्यारों की वकालत करता है जो व्यक्ति फेरा एकट के अंतर्गत करोड़ों रुपयों की जालसाजी करता है, जो व्यक्ति विदेशों में जाकर के राष्ट्रीयता के प्रतिकूल राष्ट्र को तोड़ने की साजिश करता है और खालिस्तान की मांग करता है उस व्यक्ति को इस सदन में लाया।

सहोदया, राम कृष्ण हेगड़े ने जिस तरह के कारनाम किए हैं, वे कारनाम इस देश के जनतंत्र के इतिहास को कलंकित करने वाले हैं... (समय की घंटी)... सहोदया, मैं

अधिक न कहकर, अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुलदीप सिंह आयोग बना। बेगलोर की 128 हाऊसिंग सोसायटीज को दस हजार एकड़ से ज्यादा जमीन विकसित कर मकान बनाने के लिए बेची या बांटी गई और कर्नाटक में भवन मकान निर्माण संबंधी कानून इतने पेचीदा और पुराने हैं कि सोसायटीज को सरकारी भूफसलों से अपना काम करवा पाने में भारी दिक्कत आती है जिससे बिचोलियों को बन भाई है। खुद हेगड़े सरकार ने इस समस्या के हल के लिए एक जी० बी० के० राव कमिटी बनाई की, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। इसलिये इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। शराब के ठेको के माध्यम से... (व्यवधान)... केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए इंदिरा आवास योजना के लिए ग्रामीण रोजगार के लिए और दूसरे विकास कार्यों के लिए जितने रुपए दिए गए हैं माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं माननीय उपसभापति जी हैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहता हूँ कि जब से राम कृष्ण हेगड़े मुख्य मंत्री थे तब से भारत सरकार ने किन-किन मदों में कितना रुपया दिया है कितना उनका यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना मिस-एप्रोप्रिएशन हुआ है यह सब तथ्य सदन के सामने आने चाहिए।

सहोदया मैं मांग करूंगा कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो करेप्शन करता है चाहे विरोधी दल का हो चाहे सत्ता-दल का जांच होनी चाहिए। आप कहते हैं कि राज्यपाल ने हटा दिया राज्यपाल को आदेश देते हैं। मैं पूछना हूँ यह जनता पार्टी की जब हुकुमत थी चौधरी चरण सिंह का वक्तव्य क्या आप भूल गए 1979 का एक साथ हमारी कांग्रेस की सरकारी को राज्यों में अपने राज्यपालों के माध्यम से बरखास्त किया था। आज आप जनतंत्र की बात करते हैं और जब अपने ऊपर पड़ती है तो दोषारोपण करते हैं कि राजीव गांधी की सरकार से राजीव गांधी से पूछकर सारा काम गवर्नर करता है। इस संसद को पूरा अधिकार है और संसद जो निर्णय करती है उस आधार पर गवर्नर को एकट करना पड़ता है, उसमें कोई पार्टी

नहीं है और न इसको आधार बनाया जाना चाहिए। रामकृष्ण हेगडे के पाप का बड़ा भर गया है बोम्बई जो कुछ थे वह सर्वविदित है कि वह कुछ नहीं थे और आपस में ही इस तरह यह लड़ाते रहे जैसे गलियों में लोग लड़ते हैं और इसी कारण यह सरकार बर्खास्त हो गई है।
... (समय की घंटी) ...

महोदया, कराह रही है जनता कर्नाटक की। कर्नाटक अपनी संपन्नता के लिए, अपने उद्योग के लिए अपनी उत्पादन के लिए अपने ज्ञान के लिए अपने विवेक के लिए सारे देश में मशहूर था और यह एक ऐतिहासिक स्थान है इसको न जाने कितने ऐतिहासिक क्षणों से होकर, टीपू सुलतान के समय से लेकर आज तक गुजरना पड़ा है। जिस तरह की हस्तकला हुई है जनता पार्टी के शासन काल में, कर्नाटक में, उसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जांच के लिए एक कमीशन बैठाया जाये जो जांच करे कि किस प्रकार करोड़ों रुपयों का चोटाला हुआ, जनता के टैक्स के रुपयों का गबन किया गया, व्यक्तिगत हित में उसका उपयोग किया गया और हजारों लोगों को लसीली शराब, जहरीली शराब पिलाकर के उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरह से जमीन का चोटाला किया। इन सब चोटालों की जांच के लिए केन्द्रीय कमीशन बैठे और उस कमीशन के माध्यम से जांच होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट, इस सदन में और इस देश की जनता के सामने आनी चाहिए; जिससे पता लग सके कि कितने करप्ट, कितने व्याभिचारी, कितने अत्याचारी और कितने जनता का शोषण करने वाले यह लोग हैं और फिर विवश हो करके केन्द्र सरकार की, संसद को इनका प्राधिकार देना पड़ा कि गवर्नर रूल चले। ...
(समय की घंटी) ...

मैं पुनः मांग करूंगा कि यह जांच बड़ाई जाये और जांच के माध्यम से रामकृष्ण हेगडे और कर्नाटक में उनकी सरकार की सारी सच्चाई जनता के समक्ष लाई जाये।

मैं निवेदन करता हूँ कि आप सरकार को निर्देश दें उस चेंबर पर बैठकर; सरकार जांच बैठाने के आदेश दे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

उपसमाप्ति : श्री गुलाम रसूल मट्टू ।
आप भी जैरा टाइम को देखकर के बोलिएगा ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO
(Jammu and Kashmir): Madam Deputy Chairman, I have heard with rapt attention to the speeches made here. But none of them discussed the Budget. As usual, I will confine my remarks to the Budget. I congratulate the Finance Minister who is not here—Mr. Gadhai is here. Unlike the Punjab Budget, there are certain good features in this. But alas, as many of the Members have said, this Budget should have been discussed in the State Legislature at Bangalore, but it is being discussed over here. I feel and pray that the time will soon come when democratic Government will be installed there and they will discuss the Budgets there. But, however, I find that unlike the Punjab Budget about which I spoke the other day, Mr. Gadhai has been a little liberal in the case of Karnataka and he needs to be congratulated. In the case of Karnataka Budget, I find that in the case of Education alone, there has been an increase of Rs. 170 crores from the Budgeted estimates and the revised estimates of the year 1988-89. Similarly, there has been an increase in the Economic Services, that is, agriculture and allied activities by Rs. 97 crores. There has also been an increase in Rural Development and Special Services. The total increase is Rs. 22.3 crores. There has been an increase of Rs. 162.14 crores in the Economic Services. However, I find that on the Revenue Account, compared to the revised estimates of

[Shri Ghulam Rasool Matto]

1988-89, there has been an increase of Rs. 521.43 crores which to my mind is sizeable, and the Government needs to be congratulated for this increase, and I hope that this amount will be spent in the manner that it has been intended. However, I have three grey areas and I would like the hon. Minister to react to these. Mr. Minister, there are three areas in which I feel that justice has not been done to Karnataka. Number one is with regard to the relief on account of natural calamities. As against an amount of Rs. 15.37 crores last year in the revised Estimates, this year the Budget has been kept at Rs. 6 crores only. Thus, there is a shortfall of Rs. 9.37 crores on this account. As against Rs. 15.37 crores earmarked for last year, this year they earmarked only Rs. 6 crores.

Similarly, Madam, another very important area is 'Hill areas'. In Hill areas' also, there has been a decrease of Rs. 1 crore this year compared to last year. Similarly, with regard to ecology and environment, there has been a decrease this year which is unwarranted. I hope the Government would attend to it, and at least in these areas where there has been less allocation in the Budget, that should be increased.

The second point that I want to make, Madam, is with regard to public debts. There has been a total public debt increase of Rs. 118.30 crores during the year under the Miscellaneous Capital Receipts. As against this, the spending part there is only Rs. 18 crores. So, this Rs. 100 crores where has it gone and how it has been accounted for, the Minister may kindly react to it. On the capital account there has been an increase of Rs. 103 crores, there is no doubt. But in the case of capital account on social services, there has been a decrease of Rs. 5.63 crores and general services Rs. 49 lakhs. This needs to be looked

into and I would request the hon. Minister to pay his attention to this because this is an area, we are discussing the Karnataka Assembly. With what little time I had at my disposal, I have tried to understand it. Of course, there are very good features as compared to the Punjab Budget which we have discussed the there day. But there are certain areas which need to be paid more attention.

Lastly, I would request the hon. Minister that whenever, Madam Deputy Chairman, this is a general practice, that whenever the Governor's rule is imposed in any State, a parliamentary committee is constituted. It was constituted in the case of Tamil Nadu. It was constituted in the case of Punjab. And it has been constituted in the case of Karnataka also. Incidentally, I happen to be on two of them. But we have never met and we have never been taken into confidence as to what is happening.

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:
No, no. it has not been constituted.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO:
But in the case of Punjab, I remember, it has been constituted. The point at issue is that at least when the Budget of a particular State placed under the President's rule is being discussed, at least that advisory committee of parliamentarians may also be consulted so that they can also give their opinions before a Budget is formulated. These are my observations and with these I support the Karnataka Budget.

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE (Nominated): Madam Deputy Chairman, I rise to support the Karnataka Appropriations Bill, 1989, placed before the august House today for consideration and for passing. The objects and reasons for considering this Bill have been given at page 7. Karnataka, Madam, is facing a sharp financial crisis and the Budget for the year 1989-90 shows a deficit of Rs. 176

crores and revenue deficit of Rs. 122 crores. And the pending bills are as much as Rs. 159 crores. Considering the public deficit, the total deficit comes to about Rs. 289 crores. The State Plan outlay for the year 1989-90 has been fixed at Rs. 1040 crores and the high priorities are rightly given to various developmental programmes like irrigation, drinking water, rural water supply, power sector, medical, family welfare and public health services, housing schemes, repair and construction of roads and bridges, labour and employment, welfare for women and children and backward sections, including the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This has created a budgetary gap of Rs. 176 crores. Madam sericulture is one of the very important industries in Karnataka. The small and marginal farmers are engaged in this industry and the Centre should take necessary measure to provide adequate funds to develop this industry and produce quality yarn which will enable Karnataka to compete in the international market. Karnataka State is a major exporter of raw silk and Kashmir purchases maximum silk yarn from Karnataka Government. Research work in this line is to be intensified and the plant kingdom is to be explored for finding out suitable substitutes for mulberry leaves which are in shortage. It is gratifying to note that the Government at the Centre is trying with the World Bank assistance to encourage sericulture industry in Kolar district and elsewhere in Karnataka wherever land is suitable for development because it would generate employment opportunities.

Madam, the original size of the Seventh Plan was Rs. 3,500 crores, the net Central assistance being Rs. 873.73 crores. But the budgetary position as it now stands is not very happy. And there has been an overall deterioration of State economy. In spite of receiving Rs. 700.51 crores from the Centre during the first four years of the plan, revenue has dropped for various

reasons, and one reason being large-scale evasion of excise duty on liquor.

An amount of Rs. 470 lakhs has been given as action plan for desilting of Mangalore harbour which will go a long way to help the fishermen. There is another important project with Denmark assistance, EJADRI, and Central assistance to the tune of Rs. 38 lakhs has been provided which would help the fishermen of that area to ameliorate their sufferings as far as possible.

Another point is about the capitation fee that is being charged despite a ban imposed by the Act of 1984. Capitation fees are being charged by the private medical and engineering colleges, except St. John Medical College, Bangalore. I would request the Government to take stringent measures against those who are charging capitation fees.

Lastly—Madam, it is extremely gratifying to note that pending bills have been paid by the Government.

Considering the various on-going projects which are to be completed and the projects which are to be implemented, and considering the expenditure to be incurred for the items as given in the schedule on pages 2 to 6, for the welfare of the State, I wholeheartedly support the Karnataka Appropriation Bill and I also congratulate the Government for such a good budget for the State of Karnataka.

I once again support this Karnataka Appropriation Bill, 1989. Thank you.

उपसभापति : राम अवधेश जी पांच
मिनट लीजियेगा ।

श्री राम अवधेश सिंह : आप जितना
कह दें । आपकी उदारता पर है ।

माननीया, मैं कर्नाटक के विनियोग
विधेयक पर बहस के दरमियान इसके
चरित को एक वाक्य में कह सकता हूँ।
वह यह है कि दिल्ली की सरकार ऐसे

[श्री राम अवधेश सिंह]

लालाज बीमारी से मरने वाली सरकार की हत्या की दोषी है जो मरने वाली थी लेकिन उसके बचाव में न जाकर जहर की सुई दे कर मार दिया। कोई ऐसा रोमी हो जो मरने वाला हो और आप डाक्टर बन कर बचाने नहीं गये बल्कि जहर की सुई देकर मार दिया। ऐसी सरकार की हत्या करने की दोषी यह सरकार है जो मरने वाली है। लेकिन इसमें, जो नीयत आती है वह नीयत यह है कि संसदीय जनतंत्र में केन्द्रीय सरकार में विश्वास नहीं है। संघीय ढांचे को वह चलने नहीं देना चाहती। अगर उसको इतना मासूम था कि वह मरने वाली सरकार है, जैसा यह तर्क दिया जाता है कि आपसी मतभेद से हुआ तो उसको इतना धीरज रखना चाहिए था कि उसको मरने देती। लेकिन उसकी हत्या की अपराधी हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसके मन में एक पाप था कि शायद यह सरकार बच जाए। इसकी मौका देते सदन में ट्रायल का। क्योंकि संसदीय जनतंत्र की आरम्भ है सदन का पल्लोर, शांति का पल्लोर। इस सदन के पल्लोर पर सारी चीजें तय होती हैं। सरकार बिगड़ती है, कानून बनाये जाते हैं और उसमें संशोधन होते हैं...

उपसभापति : उसका उल्लंघन भी होता है कुछ मंत्रियों की तरफ से।

श्री राम अवधेश सिंह : उल्लंघन होता है लेकिन मैं एक संसदीय जनतंत्र की ताकत बताता हूँ और वह है सदन का पल्लोर। यहाँ उसको टेस्ट करते, करने का मौका देते, केन्द्रीय सरकार अपने राज्यपाल के माध्यम से जो राज्यपाल केन्द्रीय सरकार का *

तो किसी को कहने को मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं किया, क्योंकि भारत सरकार जानती थी कि शायद वह सरकार सदन में बच जाय और तब दुबारा राज्यपाल के माध्यम से हम जो सारी खुराफात करना चाहते थे, नहीं कर सकते। जैसे उनके मन में प्लानिंग थी जैसे तमिलनाडु की सरकार की हत्या करने के बाद वहाँ पर

राज्यपाल का शासन लागू किया, उदारता से रुपया खर्च किया और उसने *

THE DEPUTY CHAIRMAN : You cannot say that. It will not go on record.

श्री राम अवधेश सिंह : *

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let me correct it. He is appointed by the President of India. Do not use such words.

श्री राम अवधेश सिंह : यह माना गया है, इस पर सदन में चर्चा हुई है।

उपसभापति : राम अवधेश सिंह जी, जब मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ तो मेरे सामने कोई मेम्बर गलत जुम्ला बोलेंगे तो उनको मैं जहर रोक्की। मैं किसी हल का उल्लंघन नहीं होने दूंगी। यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

श्री राम अवधेश सिंह : कहने का मतलब यह है कि सदन का उनको विश्वास नहीं था और अगर उनको विश्वास होता तो उनको मौका केन्द्रीय सरकार देती और राज्यपाल के जरिये जो संविधान में उनको 356 धारा का प्रमोव अस्त प्राप्त है उसका इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन 356 धारा का एकाधिकार दिल्ली की सरकार को है उस बिलेट का इस्तेमाल करके दिल्ली में बैठ कर संघीय ढांचे को तोड़ती हैं, भरोड़ती हैं भिटाती हैं। यहाँ पर पाण्डेय जी ने और कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बातें कही गई हैं और हेगड़े पर आरोप लगाए गये और उनके बारे में क्या-क्या नहीं कहा गया। मैं उस सब के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि हेगड़े साहब ने इस देश में एक ऊँचा सार्वजनिक जीवन का मानदण्ड रखा है। जब कभी उनके खिलाफ कोई टिप्पणी हुई तो दो-दो बार उस टिप्पणी की प्रतिक्रिया में बहुत मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा दिया है और देश के सामने एक ऊँचा मानदण्ड

रखा है। अगर कांग्रेसियों में हिम्मत होती तो दिल्ली से लेकर राज्य सरकार में कभी इस्तीफा देकर देश में ऊंचा मानदण्ड बनाने की कोशिश करती। जो रिपोर्ट है उसमें भी देश जान गया है कि यह सरकार दोषी है लेकिन यह दोष मानने के लिए तैयार नहीं है। बेशर्त और बेहया की तरह से खड़ी है और कहती है कि हम बेसम हैं। एक कहावत है—
कुपवा से हंसत छलनियां कहत जिसमें सहस्र छेद।
सूप से छलनी कहती है जिसमें सैंकड़ों छेद हैं कि तुम में छेद है। इतने कुंघण तुम में हैं, पाप के अपराधी हैं और आप कह रहे हैं कि यह हेण्डे साहब ने गड़बड़ की है, भ्रष्टाचार के अपराधी हैं और उन्होंने कर चोरी की है.....
(अध्यक्ष) : मैं बजट पर बोल रहा हूँ। पाण्डेय जी ने कहा कि कर चोरी के अपराधी हैं हेण्डे और उनके पीछे वाली सरकार और तब उन्होंने इस्तीफा दिया। कर चोरी का मामला, महोदया, मैंने इस सदन में उठाया, इस सदन के रिकार्ड में मैं इस मामले को लाया और वह कांग्रेसीत रखे जिसमें यह कहा गया कि केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल टैक्स यह टाटा चुरी रहा है। वे कांग्रेसीत मैंने रखे और दो-दो बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और सदन में तीन-तीन बार इस मामले को उठाया। लेकिन जो कर की चोरी हो रही है उसको रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने आंकड़े दिये कि कितना कर छुराया। तब कर चोरी को बचाने का काम यह दिल्ली की सरकार यहां * डंग से करती है। पता नहीं टाटा बराने से इनका क्या संबंध है। जनता का पैसा वह लूटे और उस पर कोई कार्यवाही न हो। महोदया, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह पूंजीपतियों की बचाते वाली सरकार इससे बड़ी * सरकार दुनिया में नहीं हो सकती है मैंने आंकड़े दिये, तथ्य दिये और टिस्को के आफिसर ने लिखा दूसरे आफिसर को यह काम जो किया जा रहा है यह इस्वीगल है, गैर-कानूनी है, इसको ठीक किया जाय। लेकिन इसे ठीक नहीं किया गया। ये आंकड़े रिकार्ड में देखे जाय। महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री.

उपसभापति : आपका समय खत्म हो गया।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ।

उपसभापति : नहीं आपका समय खत्म हो गया।

श्री राम अवधेश सिंह : एक मिनट में।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इतने * मत बनिये इतने * मत बनिये।
..... (अध्यक्ष)

THAKUR JAGATPAL SINGH: This is unparliamentary. This should not come on record.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This word will not become part of the record.

श्री राम अवधेश सिंह : *
पालियामेंटरी है।

उपसभापति : यह इसलिये नहीं रहेगा क्योंकि आपका समय खत्म हो गया है। आप अब जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं आ रहा है।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : आप इस हाउस की नहीं चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : आप कन्स्यूड कर चुके।

I have asked Shri Maheswarappa to speak.

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : अब प्वाइंट ऑफ आर्डर कुछ नहीं हो सकती। आपका टाइम खत्म हो गया। आप बैठ जाइये।

Mr. Maheswarappa, you speak. Don't listen to him.

*Not recorded.

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : आप जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है । राम अवधेश सिंह जी आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं आ रही है ।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं आ रही है । प्वाइंट ऑफ आर्डर हो या डिस आर्डर हो । आप बैठ जाइये ।

श्री राम अवधेश सिंह : *

उपसभापति : आप बैठ जाइये । आप जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है । पार्लियामेंटरी बोलिये या अन-पार्लियामेंटरी रिकार्ड में नहीं जा रहा है । आप बैठ जाइये ।

(Interruptions). Nothing will go on record.

DR. RATNAKAR PANDEY : Don't challenge the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Nothing is going on record. Yes, Mr. Maheswarappa, please speak.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA : Madam Deputy Chairman, it was really amusing to hear some of the speeches from the Treasury Benches. I wish I had the time to reply to some of the reckless allegations made against my party and my leaders. There should be some limit. Today they have gone beyond all limits of decency in attacking Mr. Ramkrishna Hegde who is not a member of this House and who is not even the Chief Minister and has not even presented this budget. The Chief Minister who presented it was Mr. Bommai who was also the Finance Minister. But no other name is taken from Karnataka except Mr. Ramakrishna Hegde.* I do not know why

they are so much afraid of Mr. Hegde. He is haunting every Congressman and the Central Government. However, I do not want to go into that. I know Mr. Hanumanthappa made certain remarks and I will come to that. I request you, Madam, to give me some more time. Heavens will not fall if I am given five minutes more. After all no Opposition Member has spoken from Karnataka in both the Houses. If I speak anything irrelevant you stop me.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I want to keep the record straight. Seven from the Opposition have already spoken.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA : But not from Karnataka.

* THE DEPUTY CHAIRMAN : If you have few Members from Karnataka, I cannot help it.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA : We are discussing the Karnataka Budget. As the only Opposition Member from Karnataka, I am requesting you to give me some more time.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am giving you time. Your time was not there. I am myself giving you time. You speak.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA : I am not saying that all the assurances given in our manifesto have been implemented. There may be some lapses. But you must be magnanimous enough to appreciate some of the achievements. I do not want to refer to many other things. I refer only to such essential things as the Karnataka Government has achieved—namely, providing drinking water. I challenge any Member from that side to show if any Congress-ruled State in the country has provided so many bore wells, so many tanks for drinking water in rural and urban villages. I will just give you the figures. We may have given more licences for arrak but if we give sufficient water throughout the State, will you not appreciate

*Not recorded.

it? I give you the comparative figures of bore wells sunk in urban villages. From 1978 to 1983, the Congress Government was there. The number of bore wells sunk during the Congress rule was 316 (urban). In Janata regime, the number was 4223. In rural areas, the number during your period of five years was 35,960 for the bore wells sunk for drinking water. In our period, the number was 53,721 for piped water supply. The number of villages covered during your period was 889; during our period it was 1,679. This is regarding drinking water.

I am giving you one more statistics. So far as power for pump-sets is concerned, Mr. Narayanasamy, you are talking so much about farmers, how many pump-sets were given power? Perhaps it is unparalleled in the history of any State. The number of agricultural pump-sets energised during your period was 2,030. During Janata period we energised 4863 pump-sets. And electricity to rural villages was hundred per cent. Electricity was given to all the villages. No village, no hamlet was left uncovered. If you spend so much amount, as Mr. Matto pointed out and he made a good point that we have provided more funds for energy, more funds for irrigation, at least compliment us. We have to carry out the on-going projects like the Krishna project and the Cauvery basin project. We want more funds. Now what is Mr. Deve Gowda crying about?

7.00 P.M.

Not much is spent on irrigation. This budget, if I may submit, is a budget for rural-oriented programmes. Out of the outlay of Rs. 1,040 crores, Rs. 667 crores, that is, 64 per cent of the budget, is allocated for the rural areas. We do care for the rural areas. Then, how much is given for irrigation? An amount of Rs. 209.40 plus Rs. 100 crores, that is, a total of Rs. 309 crores. Then, Rs. 275 crores is being allocated for power. The total comes to more than 50 per cent of the total Plan allocation for power and irrigation. We

are spending more than 50 per cent of the total allocation on power and irrigation, but our irrigation projects are not being completed. Even whatever award the Bachawat Commission gave, we were not able to utilize that water in the Krishna Basin. Our friends are quarrelling with us. At least, have funds raised to complete the projects to utilize whatever is allowed to us in the Krishna Basin.

You should all help us in appealing to the Central Government to give us more funds to complete the targets under the Krishna Basin. After all, Karnataka is in India. Just because it was ruled for six years by another party, you can't attack Karnataka, Karnataka leaders, everything in Karnataka and our party. It is not fair on your part.

SHRI V. NARAYANASAMY: Are you defending corruption?

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: No. But, in Kannada there is a proverb which means, if a donkey is lying dead in front of your house, you are not caring, but if there is a dead fly lying in front of my house, you are talking of it. That is a Kannada proverb. With your permission, Madam, let it go on record. A dead donkey is in front of your house, but you are talking of a dead fly in front of my house.(Interruptions).... The whole world knows what the charges were.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I did not understand about the donkey part of it!(Interruptions)....

SHRI B. K. GADHVI: Madam, even if he says that it is a dead donkey, I would request that it should not go on record.

....(Interruptions)....

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: It is a proverb in Kannada.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: I only quoted a proverb in Kannada.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What does it mean?

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: If a donkey is dead in front of your House, you are not caring, but if a fly is lying dead in front of my house, you are making a hue and cry. I don't say it is a corruption-free Government. I don't think there is any corruption-free Government in the whole world. Even Shrimati Indira Gandhi once said that corruption would be there so long as the sun and moon are there. ... (Time-bell rings) ... Madam, please, I have got so many points. So many charges have been made.

They talked about Mr. Ramakrishna Hegde. Whenever there was a charge made against him, when he was Chief Minister, he instituted an inquiry into it. How many Chief Ministers have done it? Any number of inquiries may be appointed—he has no objection. And, what were the charges? After all, Mr. Narayanasamy knows that some facts are distorted. Mr. Sukul distorted facts. Instead of saying ten crores, he said ten thousand crores, five thousand crores and that every day Mr. Hegde was taking Rs. 100 crores of money.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You say the correct figure: we will accept it.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: I have no time, Mr. Hanumanthappa. Both of us come from the same district. Let us go to the people. Hold elections immediately. But you are not talking of elections. (time bell rings) ... Madam, if you do not want me to speak, I will sit down.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I want you to finish within the time.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: What is going to happen to this? About the two enquiries constituted, now I can talk.

What is the charge in the first enquiry? The BDA land was proposed to be given to NRIs. It was not given even. Why are you talking about it? It was cancelled by our Government. The proposal was dropped. (Interruptions) Had he taken money, those people would not have kept quiet. The proposal has not materialised. Supposing they have given money, what has happened to those persons who have given the money? (Interruptions) Let us be fair to Mr. Hegde also. You make allegations, I don't mind. We have also made allegations against Mr. Rajiv Gandhi and so many other persons: I will not come in the way of your making allegations. What is it now? It was only a proposal for some sites to be given to NRIs. At one stage opposition was there. The Cabinet was to approve that proposal. The Cabinet did not approve it. It dropped it. Where is the need for an enquiry? All right. Still there is an enquiry. You hang him if he is found guilty. Why talk about all those things? The only issue before this Upper House and the country is "NRIs, NRIs, Ramakrishna Hegde, Ramakrishna Hegde." What is this?

The second one is about Revjit. After all, Madam, you know, it is a private transaction between two private parties on a private land. Mr. Hegde did not sell any Government land costing Rs. 50 lakhs for Rs. 3 lakhs. You make it appear that Mr. Hegde sold some Government land worth Rs. 50 lakhs for Rs. 3 lakhs. Is it a fact? It was a transaction between two private companies. The Revjit Company purchased the land.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Who are the members? What is the relationship with Mr. Hegde? (Interruptions)

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: I know the history of everyone of you. (Interruptions) A distant relative of Mr. Hegde is a partner of that company.

SHRI Y. NARAYANASAMY: You come out.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: I will come out. All right. (Interruptions) How is Mr. Hegde responsible for it? (Interruptions)

Madam, it is a serious matter. This matter has been referred to. It is not even a Government land. Even for that he was prepared for an enquiry. It was not the Bofors or something like that. It is not so big. It is between two private parties. Their allegation is that there is undervaluing of this property. One of the purchasers is one distant relative of Mr. Hegde. (Interruptions) Even if his hand is there, let it come out. The enquiry is there. A judge of the Supreme Court is the presiding officer. When the commission is seized of the matter, should they talk so much?

Except these two things, what other things are there against Mr. Hegde? He is prepared. (Interruptions)

About medical seats, a startling revelation I am making. In our private medical colleges, the Governor has got a certain number of seats reserved for his allotment. I will resign my seat if it is disproved. (Interruptions)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, I want to set the record straight. Even earlier there were Government seats. I know.

Mr. Maheswarappa knows it. The Government seats are allotted by the Governor. I am sorry. You cannot distort the facts.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: For the Government seats there are rules and regulations about how they should be allotted. But there are other seats. Do you know how many seats the Governor recommends to the private colleges for outside persons as a personal recommendation? (Interruptions) I know.

We are under President's rule. We are the victims. I want to expose this 6-month rule, how they are administering the State, how they are misruling. I am sorry our friends are not prepared to hear uncharitable things.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Maheswarappa, I gave you enough time.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: The question of time does not matter...

THE DEPUTY CHAIRMAN: It does matter. I don't know how this happens in your State, but here things go by rules and regulations. The question of time does matter however important the case might be. I have given you enough time, more than your allotted time. Now, please finish in two minutes.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: When you were not in the Chair, do you know what kind of mud-slinging they were resorting to? Did you observe that?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please finish within two minutes.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: Recently, the Governor called a meeting of the MPs. I was also present in that meeting. There was a report of too much of political interference in the administration. I asked the Governor specifically that it was reported that there was too much of political interference in administration after the Governor's rule was imposed. He did not say no to that. I swear by God when I say this.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Your friend, Mr. Chandre Gowda, has admitted that there is a lot of interference by the Janata leaders, not by the Congress leaders.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: He mentioned Deve Gowda. Not even one of us has gone to him. (Interruptions)

[Shri K. G. Maheswarappa]

I would say that we want sympathy for Karnataka. All right, as he says, the State economy is in shambles. Everything has got derailed. At that time you did not give any type of relief to the State. But now that you have taken over the administration, how is it that all types of reliefs have been cleared within five months? It looks as if by magic you got all the money and now within five months honey is flowing into Karnataka! Therefore, I finally appeal for a grant of at least Rs. 300 crores to Rs. 400 crores to the State Exchequer. (Interruptions) Don't you want to complete the Krishna River Project? Therefore, I am appealing to you finally that we are for holding early elections. October is very near. Let the Minister come out with a statement whether he is going to have extension of the President's rule or wants to hold elections. Our Party is prepared to face the election. If you hold the elections, we will certainly go to the people. Therefore, why should you perpetuate the Governor's rule or the Centre's administration? Not even one man from your party has complimented the State Government about the functioning of the Panchayati Raj institutions there. No one had the grace to congratulate our Government at least on that. Your External Affairs Minister, Mr. P. V. Narasimha Rao, at a meeting at Bangalore where more than lakh of people had gathered openly congratulated the Karnataka Government and Mr. Hegde. If you want I will bring the record tomorrow. Your own senior Minister has congratulated the Karnataka Government for so many other progressive measures it had taken and you don't have the grace to congratulate us. Mr. Pandey with his Mantram Japan tried to hammer everyone of us. He is a big Pandit from Kashi. A Kashi Pandit should not go to that level of talking.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. The Constitution (Sixty-third Amendment) Bill, 1989.

II. The Constitution (Sixth-fourth Amendment) Bill, 1989.

III. The .. Constitution (Sixty-fifth Amendment) Bill, 1989.

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (Sixty-third Amendment) Bill, 1989, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th August, 1989, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (Sixty-fourth Amendment) Bill, 1989, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th August, 1989, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

(III)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (Sixtyfifth Amendment) Bill, 1989, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th August, 1989, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Madam, I lay a copy of each of the Bills on the Table.